सामाजिक न्याय की ओर मोदी सरकार के बढते कदम

(Modi Government's Increasing Steps Towards Social Justice)

डॉ. संजय कुमार यादव
सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
बाबा मोहनराम किसान (सह-शिक्षा) स्नातकोत्तर महाविधालय
मिलकपुर - भिवाड़ी, जिला-अलवर (राजस्थान) 301018

सारांश

भारत में आज भी कई लोग अपनी कई मूल जरुरतों के लिए न्याय प्रकिया को नहीं जानते, जिसके अभाव में कई बार उनके मानवाधिकारों का हनन होता है और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। क्योकि भारत में अशिक्षा, ग़रीबी, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता ज्यादा है। ओर इन सभी भेदभावों के कारण सामाजिक न्याय बेहद विचारणीय विषय हो गया है। और वर्तमान मोदी सरकार सामाजिक न्याय के विचारणीय विषय को धरातल पर उतरने के लिए विभिन्न योजनाओ को अमली पहना रही है

आज तक पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को मानकर काम किया था लेकिन केन्द्र सरकार ने सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण के लिये नये मापदंड तैयार किये हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई कोशिश के अंतर्गत जिले को भी एक केन्द्र माना है। और कहा अगर जिला ही पिछड़ा होगा, कनेक्टेड नहीं होगा तो वहाँ रहने वाला हर नागरिक दूसरों की तुलना में पिछड़ जाएगा। इसलिये प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के 115 जिलों को चुना गया है और उनके विकास की अलग से योजना तैयार की गई है। जिससे इन पिछड़े जिलों में अब नई सोच के साथ काम हो रहा है

भारत में सामाजिक न्याय के प्रयास

सामाजिक न्याय के संदर्भ में जब भी **भारत** की बात करते है तो हम देखते हैं कि हमारे **संविधान** की प्रस्तावना और अनेकों प्रावधानों के द्वारा इसे सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भारत में फैली जाति प्रथा और इस पर होने वाला स्वार्थपूर्ण भेदभाव सामाजिक न्याय को रोकने में एक अहम कारक सिद्ध होता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास आयोग जैसी कई सरकारी तंत्र एवं लाखों स्वयं सेवी संगठन हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि समाज में भेदभाव से कोई आम इंसान पीड़ित न हो। भारत में आज भी कई लोग अपनी कई मूल जरुरतों के लिए न्याय प्रकिया को नहीं जानते जिसके अभाव में कई बार उनके मानवाधिकारों का हनन होता है और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। आज भारत में अशिक्षा, ग़रीबी, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता ज्यादा है। इन्हीं भेदभावों के कारण सामाजिक न्याय बेहद विचारणीय विषय हो गया है।

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने2014 में स्पष्ट कहा था कि यह सरकार गरीबों और वंचितों की सरकार है जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने के लिये हर सम्भव प्रयास करेगी। मोदी सरकार ने तमाम योजनाएँ और कार्यक्रम इसी लक्ष्य को मध्यनजररखते बनाये और लगातार पिछले छः साल में जो योजनाएँ बनीं और कार्यान्वित हुईं उनका लाभ अब निम्न वर्गों तक पहुँचने लगा है और स्पष्टरूप में दिखने लगा है।

सामाजिक न्याय की नई सोच

भारत में सामाजिक आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिये समूह आधारित उपागम (ग्रुप बेस्ड अप्रोच) को अपनाया गया। सविधान निर्माताओ ने समाज के पिछड़ेवंचित दलित और हाशिए के समाज के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन और सशक्तीकरण के लिये उन्हें विभिन्न समूहों के रूप में चिन्हित किया और सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण को अपनाया। हमने स्वीकारा कि जब शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुँच गये लोगों को बराबरी पर लाया जाएगा तो शेष समस्याएँ भी समाप्त हो जाएँगी। यद्पि ऐसा पूरी तरीके से नहीं हुआ और परिणाम स्वरुप दूसरे कानून भी बनाने पड़े जिसमें दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने वाला कानून प्रमुख है।

1950 में सिर्फ अनुसूचित जाति-जनजाति के लिये लागू किये गये आरक्षण का दायरा बढ़ाना पड़ा। सरकार ने सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये भी जाति को आधार मानकर 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की । अब लाखों-करोड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े तबके के युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके नौकरी के लिये प्रयास कर रहे हैं तो नई समस्याएँ सामने आ रही हैं। सरकारी नौकरियों की संख्या तो लगभग तीन करोड़ तक सीमित है जबकि सामान्य स्नातक से लेकर आईआईटी, आईआईएम और पीएचडी तक पढ़ाई करने वाले दलित और पिछड़े समाज के युवाओं की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। इसलिये वंचित और हाशिए के समाज के लिये नई सोच विकसित कर काम करने की जरूरत है। और अब ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हैI

14 अप्रैल, 2018 को नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पुराने रास्तों पर चलते हुए आप कभी भी नई मंजिलों तक नहीं पहुँच सकते हैं। पुराने रास्तों से नई चीजें नहीं हासिल होती हैं। इसलिये हमारी सरकार नई सोच के साथ काम कर रही है।"

मोदी सरकार की थीम है- सबका साथ, सबका विकास। इसमें प्रयास है कि समाज की उस अन्तिममहिलाओकोहर वह सुविधाऐमिले जिसने आजादी के सत्तर साल बाद भी विकास की नई किरण नहीं देखी है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लालकिले के प्राचीर विश्व के सबसे बड़े आर्थिक भागीदारी के कार्येक्रम जिसका नाम प्रधानमंत्री जन-धन योजना की घोषणा की इस अवसर को एक उत्सव के तोर पर मानाने की बात कही जिससे गरीब जनता कुचक्र से निजात पाने जा रही हैमोदी सरकार के गठन के बाद ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की गई जिसको सम्पूर्ण भारत में 28 अगस्त 2014 में लागू किया गया जिससे वित्तीय समावेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। हर उस व्यक्ति का खाता खुला जिसे सरकारी योजना का लाभ मिलता था। करीब तीस करोड़ अकाउंट आज तक खोले जा चुके

हैं। ये अकांउट उन लोगों के हैं जिनके अब तक खुले नहीं थे और इनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज वंचित समाज के इन लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से मिलने वाला पैसा सीधे अकांउट में मिल रहा है और उन्हें किसी बिचौलिये को हिस्सा नहीं देना पड़ रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को लोन वितरित किये गये, जिनमें दलित, पिछड़े और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है ।

उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के गरीब परिवारों कि महिलाओ के चेहरो पर ख़ुशी लाने के उद्देश्य प्रधानमत्री मोदी के नेत्रत्व

वाली केन्द्र सरकार ने 1मई 2016 को यूपी के बलिया से शुरू की जिससे करोडो अभावग्रस्त और साधनहीन महिलाओ के रसोई घर में क्रांति आई । इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओ को मुफ्त में एलपीजी गैस कैन्क्सन दिए गए जिसकी प्रसांगिकताआज भी बनी हुई है ।

उद्यमिता को प्रोत्साहन

'स्टैंड अप योजना' में दलितों , आदिवासियो और पिछड़े समाज के युवाओं को अपने व्यवसाय के लिये आर्थिक मदद की योजना 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई। इस योजना के तहत देश की एक लाख पच्चीस हजार बैंक शाखाओं के माध्यम से दो उद्यमियों को व्यापार में आर्थिक मदद की बात की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वंचित वर्ग के लोगों को अपना उद्योग प्रारम्भ करने में सहायता मिली है। हाल ही में इस योजना में कुछ परिवर्तन किए गये हैं, जिसके तहत अब बीस लाख रुपए तक भी सहायता मिल रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से **दलित वेंचर कैपिटल फंड** की स्थापना की गई जिसके तहत दलित समाज के उद्यमियों को व्यापार में पूँजी की सहायता का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत भी दलित समाज से आने वाले कई उद्यमियों को लाभ पहुँचा है। दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मिलिंद काम्बले ने साफ किया है कि हर शिक्षित दलित को नौकरी मुहैयानहीं कराई जा सकती इसलिये सूक्ष्म-उद्यमी बनने का प्रयास सबको करना चाहिए और गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्रवेश की कोशिश करनी चाहिए।

पूर्व वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने 2018 के अपने बजट भाषण में अनुसूचित जातियों के विकास के लिये 56,619 करोड़ रुपए और जनजातियों के विकास के लिये 39,135 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। और उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए की राशि लोन के तौर पर देने का लक्ष्य रखा है। ऐसे समय में जब नौकरियाँ सीमित हैं तो उद्यमिता की तरफ ही हमें आगे बढ़ना होगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर केंद्र कीमोदी सरकार ने कई योजनाएँ बनाई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये। आज दलित और पिछड़े समाज के हजारों युवा मुद्रा, स्टैंड अप और अन्य योजनाओं के माध्यम से अपना रोजगार शुरू कर चुके हैं और लाखों लोगों को नौकरी देने में भी सफल हुए हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने "स्वच्छता उद्यमी योजना" शुरूआत की है जिसका शुभारम्भ 2 अक्टूम्बर 2014 को गाँधी जी के जन्मदिवस पर माननीय राज्य मंत्री सामजिक न्याय अधिकारिता श्री सुदर्शन भगत जी ने किया जिसका उदेश्य स्वच्छता एवम् सफाई कर्मचारियो ओर मुक्त मैंनवल स्केवेजरो को जीवन यापन करना जिससे स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

संवैधानिक उपबन्ध

मोदी सरकार ने अप्रैल 2016 में दलित उत्पीड़न को रोकने वाले कानून को और भी सख्त बनाते हुए केन्द्र सरकार ने कोशिश की ताकि दलित समाज और भी सुरक्षित महसूस कर सके। सरकार ने ससंद में 123वाँ संविधान संसोधन प्रस्तुत किया है जिसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये एक नये आयोग के गठन की बात कही गई है। इस आयोग के बनने के बाद पिछड़े वर्ग को और भी कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

अन्य प्रयास

केन्द्र सरकार ने दलित हितों के लिये लड़ने वाले महान नेता डॉ. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े पाँच स्थानों को **"पंच तीर्थ"** कहकर सम्बोधित किया और उनके विकास के लिये तेजी से काम आगे बढ़ाया। दिल्ली में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है जहाँ रिसर्च और अन्य अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। डॉ. अम्बेडकर के दिल्ली स्थित अलीपुर वाले आवास को सौ करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है। लंदन में जहाँ डॉ. अम्बेडकर रहे थे उस घर को भी खरीदा गया है। भारत सरकार ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से सौ विद्यार्थियों को अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की सैर कराई जाती है जिससे वे अम्बेडकर के विचारों से और

प्रेरणा पा सकें।

महिलाओं के लिए

आज महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में आगे आई हैं और उनकी स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बड़ा तबका ऐसा है जिसके लिये काम किया जाना शेष है। पहले गाँवों में रहने वाली, अनपढ़ महिला वह चाहे किसी भी समाज से आती हो किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाती थी। मोदी सरकार से पहले ऐसी महिलाओं के लिये कोई कारगर योजना शायद ही बनी हो। मोदी सरकार ने **"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"** योजना के तहत शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना सफल रही है। इस योजना की शुरूआत 2015 में की गई थी। इस स्कीम के तहत दो साल के भीतर ही देश में लड़कियों के नाम पर 1.26 करोड़ खाते खोले गये। जिसमें 19.183 करोड़ रुपए जमा हुए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली हर महिला के लिये मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की जिसके तहत उन्हें गैस सिलेंडर और चूल्हा दिये जाने की व्यवस्था की गई है। अब तक चार करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुँच चुका है। इस बजट में आठ करोड़ महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य 2019 तक रखा गया है।

दिव्यांग कल्याण

सरकार ने इन में दलित आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के साथ-साथ ऐसे अन्य वर्गों को भी चिन्हित करने और उनके लिये कारगर योजना बनाने का काम किया है जो विकास की दौड़ में विभिन्न कारणों से साथ नहीं आ सके। शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द '**दिव्यांग**'कहकर सम्बोधित किया और उनके लिये बड़े-बड़े कैम्प आयोजित किये गये और वहाँ उन्हें मुफ्त में कृत्रिम अंग, हियरिंग एड, ट्राइसाइकिल आदि दिये गये। जहाँ 1992 से 2012 के बीच ऐसे 100 कैम्प आयोजित किये गये थे वहीं 2014 से 2016 के बीच ही 100 से ज्यादा कैम्प आयोजित किये गये। जिन दो कैम्पों में प्रधानमंत्री का खुद रहना हुआ वो गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए और उनमें दस हजार से ज्यादा दिव्यांगों को मदद की गई।

सुगम्य भारत कार्यक्रम के तहत हर सरकारी इमारत को दिव्यांगों को सुगम्य बनाने के लिये उसमें रैंप और अन्य व्यवस्थाएँ की गई हैं। डॉ अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाङ्मय का ब्रेल लिपि में अनुवाद किया गया है जो केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

वरिष्ठ नागरिक

वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिये कई नई योजनाएँ शुरू की हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2017 में **वय वंदना योजना** शुरू की जो वरिष्ठ नागरिको के बीच काफी लोकप्रिय योजना रही और कई योजनाओं के पैसे सत्तर से अस्सी फीसदी तक बढ़ा दिये हैं। इस योजना के तहत 2014-15 और 2015-16 में 42 करोड़ रुपए इकतालीस हजार वरिष्ठ नागरिकों पर खर्च किये गये और 2017 में 29 करोड़ रुपए खर्च किये गये थे। वरिष्ठ नागरिकों पर बनी राष्ट्रीय नीति को बदलती जनसंख्या के हिसाब से बदला गया है जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक जरूरतों और बदलते सामाजिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिये हर वर्ष कई लोगों को वयोश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। एक योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड से जुड़े हुए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत सी सुविधाएँ मिलेंगी। जो उनकी सामाजिक आर्थिक जरुरतो और बदलते सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाई गयी है !

घूमन्तू जातियाँ

घूमन्तू जातियों की समस्याओं के निवारण के लिये एक अलग आयोग का गठन किया गया था। नानाजी देशमुख के नाम से एक योजना शुरू की गई जिसके तहत घूमन्तू जाति के युवाओं के लिये छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है

छात्रवृत्ति

प्रीमैट्रिक में पढ़ने वाले दलित पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को कारगर तरीके से स्कॉलरशिप बाँटी गई है। 2014-15 और 2015-16 में 49 लाख 24 हजार सात सौ दलित छात्रों को 1038.73 करोड़ रुपए और 2016-17 में रुपए 344.28 करोड़ करीब साढ़े 13 लाख से अधिक दलित छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप में दिये गये। करीब पचास लाख ओबीसी छात्रों को 230 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 2014-15 और 2015-16 में दी गई। 2016-17 के दौरान 106 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप ओबीसी छात्रों को दी गई। इसी तरह मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को जो दलित और पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हें सहयोग किया गया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दलित समाज के 3476 छात्रों को 2014-15 और 2015-16 में करीब 50 करोड़ की धनराशि दी गई और 2016-17 में करीब 1310 छात्रों को 18.41 की राशि बाँटी गई। 2018-19 में मिलने वाली छात्रवृति के फंड 1643 करोड़ की व्यवस्था की ।आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग-जिसमें अगड़ी जातियों के युवाओं के लिये भी पहली बार 2014-15 में पोस्ट-मैट्रिक लेवल पर डॉ अम्बेडकर के नाम से स्कॉलरशिप शुरू की गई। 2014-15 और 2015-16 में 50,000 विद्यार्थियों के लिये दस करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई और 2016-17 में भी करीब इतनी ही धनराशिबाँटी गई। शोध कर रहे दलित समाज के करीब दो हजार विद्यार्थियों को 2016-17 में 196 करोड़ की राशि दी गई। ओबीसी समाज के छात्रों के लिये पहली बार नेशनल फैलेशिप की शुरुआत की गई है।

(5)

विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले दलित विद्यार्थियों के लिये भी प्रावधान बनाकर उन्हें आर्थिक मदद की गई। ऐसी ही योजना पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिये भी पहली बार इस सरकार में बनाई गई है। दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये छात्रावास बनाने की योजना को नये तरीके से बनाया गया जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुँच सके। पिछड़े और दलित विद्यार्थियों की कोचिंग के लिये दी जानी वाली धनराशि में बढ़ोत्तरी की गई है।

आयुष्मान भारत योजना

गरीब और वंचितों को स्वास्थ्य सुविधा आसानी से मुहैया कराने के लिये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरूआत1 अप्रैल 2018 को मोदी सरकार सरकार द्वारा की गई है।इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को डॉ भीम राव अम्बेडकर की जयंती पर छतीसगढ़ के बीजापुर जिले से पहले **हेल्थ और वेलनेस** सेंटर का उद्घाटन करके इस योजना की शुरुआत की। इस तरह के डेढ़ लाख सेंटर देश में बनाये जाएँगे। इस योजना के तहत देश के दस करोड़ परिवारों यानी करीब पचास करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँगी और उनका पाँच लाख तक का बीमा भी किया जाएगा। इससे पहले भी सरकार वंचित समाज की बेहतरी के लिये स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन हजार से ज्यादा जन औषधि केन्द्र स्थापित कर दवाइयाँ कम मूल्य पर बेच रही है। स्टैंट की कीमत नियंत्रित की गई है और वंचितों के लिये मुफ्त डायलिसिस की विशेष योजना शुरू की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन अभियान

सामान्य रूप से मध्य और उच्च वर्ग के लोगों के यहाँ तो शौचालय होता है लेकिन समाज का वह वर्ग जो अपने लिये दो जून की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाता, वह अपने लिये शौचालय कैसे बनाएगा। सरकार अब तक छह करोड़ शौचालयों का निर्माण करवा चुकी है। इस वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालयों का और निर्माण किये जाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री जन आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम शहरो में रहने वाले लोगो को उनकी क्रिया शक्ति के अनुरूप घर प्रदान किये जाने कि व्यवस्था कि गई है प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण आवास योजना दोनों क्षेत्र के लिए है। इस योजना का शुभारम्भ 25 जून 2015 को हुआ जिसका उद्देश्य 2022 तक घर उपलब्ध करना है। जिसके तहत देश में हर गरीब का अपना घर हो इसके लिये भी सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। इसके साथ ही साथ बिजली की समस्या से निपटने के लिये प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना शुरू की गई है।

<u>जिले को केन्द्र मानकर काम</u>

आज तक पिछड़ेपन का आधार सिर्फ जाति को मानकर काम किया था लेकिन मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय और सामाजिक समरस्ता के लिये नये मापदंड तैयार किये । प्रधानमंत्री ने अपनी नई कोशिश के तहत जिले को भी एक केन्द्र माना है। अगर जिला ही पिछड़ा होगा, कनेक्टेड नहीं होगा तो वहाँ रहने वाला हर नागरिक दूसरों की तुलना में पिछड़ जाएगा। इसलिये प्रधानमंत्री के निर्देश पर देश के 115 जिलों को चुना गया और उनके विकास के लिए अलग से योजना तैयार की गई । और आज इन पिछड़े जिलों में नई सोच के साथ काम हो रहा है।

केन्द्र सरकार कोशिश कर रही है कि समाज के सभी वर्गों और विशेषकर उन तबकों के लिये जो वंचित और हाशिए पर हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह ईज ऑफ लिविंग का वातावरण तैयार किया जाए। और इसीलिये इस बार के बजट में कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना तक बढ़ा दिया गया है जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुँचाया जा सके। किसान की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य इस सरकार कि प्राथमिकता है।

केन्द्र सरकार समाज के सभी वर्गों को एक स्तर पर लाकर एक समानता मूलक समाज के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक समरसता के सिद्धान्त को आधार मानकर सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रावधान बनाकर वंचित, दलित, शोषित समाज को सशक्त बनाने का अथक प्रयास किया है साथ ही उनके लिये उद्यमिता का वातावरण बनाया है जहाँ वे खुद तो काम शुरू कर ही सकें साथ ही समाज के दूसरे लोगों को भी काम पर लगा सकें। मोदी सरकार ने 2022 तक एक नये भारत (न्यू इंडिया) बनाने का जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिये वह भरपूर प्रयास कर रही है। समाज का वो वर्ग जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से पीछे छूट गये है उनके सशक्तीकरण के लिये विशेष प्रयास मोदी सरकार द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

सामाजिक न्याय व सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए न केवल भारत अपितु विश्व स्तर पर आज भी अथक प्रयास किये जा रहे है और इसी का परिणाम है की U.N.O. की महासभा ने 26 नवम्बर को 20 फ़रवरी को प्रति वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने कि मंजूरी दी ओर पहली बार 2009 में विश्व सामजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोज़गारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है ठीक इसी प्रति वर्ष प्रकार भारत सरकार भी ये दिवस मानती है जिसका उद्देश्य विश्व सामाजिक न्याय से मिलते-जुलते है l

संदर्भ

1. विश्व सामाजिक न्याय दिवस,फ़रवरी, 2017
2. गाँधी, डॉ. जगदीश। विश्व सामाजिक न्याय दिवस (20 फ़रवरी)
3. वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
4. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
5. सामाजिक न्याय मंच मासिक पत्रिका